captive units of the five steel companies. They produce 80 lakh tonnes a year. Most of their ore was exported to Japan. With world-wide recession in the steel industry, Japan has cut down its import of iron ore from India. Besides, other interested countries insist on a higher shipping capacity from Paradip port, the only outlet for the Chaibasa iron ore. Paradip is capable of handling only sixty thousand D.W.T. for shipping whereas the importing countries would like to have about one lakh D.W.T. capacity. Unless Paradip capacity is improved, the importers are not interested to lift iron from Paradeep.

With their captive mines fully mechanised, steel plants in the country are no more interested in ore from private mines. As a result, about 1),000 workers of private mines are thrown out of employment. I request the Government to take immediate steps to improve the shipment capacity of Paradip port from the present sixty thousand D W.T. to a minimum of one lakh D.W.T Necessary arrangements should also be made to export iron ore from Paradip port procured from Chaibas region. Suitable employment should be provided to the 10 000 workers who are out of job at present. The steel plants should be advised to increase lifting of iron ore from those mines.

(iii) Need to provide relief measures to farmers whose crops were affected by recent hailstorms.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न भागो में ओले पड़ने से फसलों को भारी क्षति हुई है जिससे किसानों के समक्ष घोर संकट उत्पन्न हो गया है। ओले पड़ने से करोड़ों रुपये की फसल बरबाद हुई है। ऐसी परिस्थिति में किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार को शीघ्र आवश्यक कदम उठाने चाहिए। किसानो की लगान माफ कर दी जानी चाहिए और बरबाद हुई फसलों का मुआवजा देने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए। किसानों के समक्ष जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, उसके निवारण हेतु सरकार को सक्रियतापूर्वक राहत कार्यों को आरम्भ करना चाहिए।

(iv) Doordarshan facilities for Chitorgarh district of Rajasthan.

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तोड़गढ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) जिले में दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। अभी हाल ही में सरकार की यह घोषणा भी थी कि 1984-85 में देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी, मैं सरकार से मांग करूंगी कि चित्तौड़गढ़ एक ऐतिहासिक नगर है। जहां के कण-कण में शक्ति तथा भक्ति का इतिहास छिपा पडा है। जहां हजारों पर्यटक देश तथा विदेश से आते है। यह क्षेत्र शिक्षा तथा विकास की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। यहां के नागरिक चारों तरफ दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध होने वाली है, जब यह सुनते है और यह सुनते है कि कोटा, भीलवाडा उदयपुर, अजमेर में सुविधा होगी किंतु चित्तौडगढ़ वंचित रह जाएगा तो बड़ी निराशा होती है। अत: मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि चित्तोड़गढ़ को भी इस वर्ष 1983-84 में दूरदर्शन से जोड़ा जाए।

(v) Protection of Wokers from exploitation in Surat Textile Industry (Gujarat)

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar) : It is a matter of great concern that the majority of 15,000 migrant workers from Orissa, employed in Surat textile industry, Gujarat are working under